

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक प्रथम जनवरी, 2020

संख्या का०आ० 2/ह०अ० 11/1994/धा० 209/2020.— हरियाणा पंचायती राज (संचार टावर विनियमन) नियम, 2012 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11), की धारा 209 की उप-धारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों यदि कोई हों, सहित, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज (संचार टावर विनियमन) संशोधन नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा पंचायती राज (संचार टावर विनियमन) नियम, 2012, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :
परन्तु ऐसा निरसन—
 - (क) निरसन के प्रभावशील होने के समय अप्रवृत्त या अविद्यमान किसी बात को पुनरुज्जीवित नहीं करेगा; या
 - (ख) इस प्रकार निरसित नियमों के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा; या
 - (ग) इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा; या
 - (घ) इस प्रकार निरसित नियमों के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति समयहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा; या
 - (ङ.) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समयहरण या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण, विविध कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा;

तथा कोई ऐसा अन्वेषण, विविध कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और कोई ऐसी शास्ति, समयहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकता है मानो उक्त नियम निरसित नहीं किए गए थे।

सुधीर राजपाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 1st January, 2020

No. S.O. 2/H.A. 11/1994/S. 209/2020.— The following draft of the rules further to repeal the Haryana Panchayati Raj (Regulation of Communication Towers) Rules, 2012 which the Governor of Haryana proposes to repeal in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994(11 of 1994), is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the following draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Development and Panchayats Department, Chandigarh, from any person with respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Panchayati Raj (Regulation of Communication Towers) (Amendment) Rules, 2019.
2. The Haryana Panchayati Raj (Regulation of Communication Towers) Rules, 2012, are hereby repealed:
Provided that such repeal shall not—
 - (a) revive anything not in force or existing at the time at which the repeal takes effect; or
 - (b) affect the previous operation of the rules so repealed or anything duly done or suffered thereunder;
or
 - (c) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the rules so repealed; or
 - (d) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed under the rules so repealed; or
 - (e) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;
and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said rules had not repealed.

SUDHIR RAJPAL,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.